जर्मनी के निर्माताओं, रूपांकनकारों और परामर्शदाताओं की फर्मों के एक समूह ने इस इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करने हेतु अभिरुचि दिखाई है । इस अध्ययन के लिए पश्चिम जर्मनी के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत धन की व्यवस्था करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजा गया धन

2140. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का संशोधन होने के बाद रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के आधार पर पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों और शाखाओं ने अलग-अलग रायल्टी, लाभ, लाभांश, तकनीकी शुल्क, ब्याज आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विदेशों को जो धन भेजा है उसका देश-वार, कम्पनी-वार और औद्योगिक-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना पूछी गई है वह बहुत व्यापक स्वरूप की है । फिर भी इसे यथा-संभव अधिक से अधिक सीमा तक इकट्ठी करके सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Proposal to expand Rourkela Steel Plant

2141. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) is there any proposal for expansion of Rourkela Steel Plant and establishing any ancillary industries therein; and

(b) if so, the total investment on that account and the employment potentialities therein and the year of implementation?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) There is no proposal for the expansion of the Rourkela Steel Plant, under consideration of the Government. The ancillary industries near the Steel plants are also not established by the Central Government but by entrepreneurs, although their establishment and growth is encouraged by the Public Sector Steel Plants.

(b) Does not arise.

Levy of Export Duty on Fish Meal

2142. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Collector of Appeals, Bombay, gave clear orders, in one case of exports of fish meal, that there is no export duty of Rs. 125/- per tonne leviable on fish meal;

(b) whether in spite of such clear orders, the Collector of Customs are collecting export duty as stated above, thereby causing financial blockage of exports and unnecessary appeals; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to ensure that Collectors of Customs act in accordance with the orders of the Collector of Appeals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The question of whether an annulment or modification of the said decision of the Appellate Collector should be sought for, under